

केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी:
सरकार के मुखिया के रूप में सेवा के 25 वर्ष
6 अक्टूबर 2026

7 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक है, भारत के लोकतंत्र की शक्ति का परिचायक है। इस दिन का ये स्पष्ट संदेश है कि यदि राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से, साफ नीयत और स्पष्ट नीतियों के साथ, जनसेवा की जाए तो जनता निरंतर समर्थन करती है।

कल 7 अक्टूबर 2026 को, माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार के मुखिया के रूप में, लगातार सेवा के 25 वर्ष पूरे करने वाले हैं। इन 25 वर्षों में उन्होंने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है।

संवैधानिक पद पर, 25 वर्षों का ये कालखंड, पद से भी आगे सेवाभाव से निस्वार्थ कर्म की अनवरत यात्रा है। पद बदला, दायित्व बढ़ा, परिस्थितियां बदलती गईं, लेकिन राष्ट्रसेवा का कर्मयोग निरंतर चलता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वयं से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है। अपने सपनों को राष्ट्र के सपनों के साथ कैसे आत्मसात करके जिया जाता है, ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है।

श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। इस पूरे कालखंड में, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, निर्णय, नीति, राष्ट्र प्रथम और नागरिक प्रथम की कसौटी पर खरी उतरी। गरीब कल्याण हो, वंचितों का उत्थान हो, किसानों का सशक्तिकरण हो, वीमेन लेड डवलपमेंट का आग्रह हो,

टेक्नॉलॉजी का लोकतांत्रिकरण हो, युवाओं के लिए अवसरों का निर्माण हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति स्पष्ट विजन हो या फिर विश्व के साथ संबंधों का एक नया अध्याय लिखना हो, राष्ट्र प्रथम ही माननीय प्रधानमंत्री जीके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रही है।

पहले गुजरात और फिर देश ने भी प्रधानमंत्री जी की इस निष्ठा को देखा, परखा और फिर उसके साथ खुद को जोड़ा है। यही कारण है कि गुजरात ने तीन बार उनके नेतृत्व को प्रचंड जनादेश दिया। और पिछले तीन लोकसभा चुनावों में, देश ने भी उनके संकल्प और सेवाभाव को अपने ऐतिहासिक जनादेश से सम्मानित किया है। ऐसा सौभाग्य, ऐसा आशीर्वाद, लोकतांत्रिक विश्व में बहुत ही कम लोगों को मिल पाया है।

25 वर्ष की इस लोकतांत्रिक यात्रा में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां नए तरीके से, नए विचार के साथ काम शुरू न हुआ हो। जहां कोई नई पहल शुरू न हुई हो या अप्रासंगिक हो चुकी व्यवस्था को बदलने का प्रयास न हुआ हो। ऐसा कोई सप्ताह ढूंढना मुश्किल है, जब प्रधानमंत्री जी ने किसी योजना का आरंभ न किया हो, कोई संस्थागत निर्णय न लिया हो या फिर किसी बड़े परिवर्तन की दिशा में कदम न बढ़ाया हो।

इस कालखंड का आकलन केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि सरकारों की कार्यसंस्कृति में आए परिवर्तन से भी करना आवश्यक है। सामान्य तौर पर सरकारों में रिफॉर्म से बचने की प्रवृत्ति रहती थी, क्योंकि रिफॉर्म के राजनीतिक जोखिम भी होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक हितों की चिंता किए बिना राष्ट्रनीति को ऊपर

रखा। उन्होंने दिखाया कि रिफॉर्म केवल कानून बदलना नहीं है, बल्कि समाज को साथ लेकर चलने की प्रक्रिया भी है। गैस पर सब्सिडी छोड़ने की अपील हो, स्वच्छता का आह्वान हो, फिटनेस का आग्रह हो, वोकल फॉर लोकल हो, खादी को अपनाने की अपील हो, डिजिटल लेनदेन का आह्वान हो, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो सरकारी अभियानों से भी आगे बढ़कर एक जन-आंदोलन बनकर सफल हुए हैं। ये जनभागीदारी से रिफॉर्म का वह मॉडल है, जो नागरिकों के भीतर कर्तव्य भाव जगाकर अपेक्षित परिणाम लाता है।

जब वर्ष 2001 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, तब गुजरात, कच्छ में आए भीषण भूकंप से प्रभावित था। इसके बाद एक गंभीर चक्रवात की स्थिति भी बनी थी। उनके सक्षम नेतृत्व ने समूचे गुजरात को ऐसे प्रेरित किया, कि कच्छ फिर से जीवंत हो उठा और गुजरात ने विकास की नई राह पकड़ ली।

मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने, बिजली, पानी और कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी। ज्योतिग्राम योजना के माध्यम से खेती के लिए दी जाने वाली बिजली की व्यवस्था को ग्रामीण घरों और दूसरे उपभोक्ताओं से अलग किया गया। इससे गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हुई और किसानों को सिंचाई के लिए तय समय पर बिजली मिली। अलग फार्म फीडर्स की व्यवस्था बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू हुई।

गुजरात में अपने सेवाकाल के दौरान प्रधानमंत्री जी ने, पानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। सुजलाम-सुफलाम और साउनी योजना जैसे अभियानों से गुजरात के उन क्षेत्रों तक भी पानी पहुंचा, जहां अनेकों पीढ़ियों ने सिर्फ पानी का अभाव ही देखा था। इसके कारण, गुजरात का कृषि उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार, उस दशक में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 10 प्रतिशत के आसपास सतत बनी रही। लेकिन इससे भी बड़ी सेवा ये हुई, कि लोगों को फ्लोराइड रहित पेयजल सुलभ होने लगा।

मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने निवेश और औद्योगीकरण के मामले में भी गुजरात को अग्रणी बनाया। वर्ष 2003 में शुरू हुआ, वाइब्रेंट गुजरातसमिट, निवेशकों के सम्मेलन से आगे बढ़कर सरकार, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को साथ जोड़ने का एक माध्यम बना। इसके बाद अन्य राज्यों ने भी इस मॉडल को अपनाया।

गुजरात में ही, सरकार और नागरिक को और निकट लाने के लिए स्वागत जैसासफल प्रयास हुआ। इसमें मुख्यमंत्री, खुद लोगों की समस्याएं सुनते थे। वर्ष 2010 में इसेयूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवॉर्डभी मिला और बाद में यह राष्ट्रीय स्तर पर, प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म की प्रेरणा बना।

गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री की विकासपरक नीतियों ने पूरे विश्व में गुजरात मॉडल को चर्चित कर दिया। इस कालखंड में गुजरात की GSDP, लगभग सवा लाख करोड़ रुपए से बढ़कर, 2025-26 में

लगभग 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस दौरान गुजरात की मैन्युफेक्चरिंग ताकत में तो कई गुना वृद्धि हुई ही, GDP में कृषि की हिस्सेदारी भी, 2000-01 के 3.6% से बढ़कर 2023-24 में 7.6% तक पहुंच गई। 2001 के बाद से गुजरात में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, 5% से बढ़कर 2025 में 15% तक पहुंच चुका है। इसी अवधि में गुजरात का निर्यात, करीब 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात में टेक्नोलॉजी का समावेश, पारदर्शी व्यवस्था और समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने की एक नई कार्य-संस्कृति का निर्माण हुआ। उन्होंने जो गुजरात मॉडल विश्व को दिया है, वो सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास का प्रतिबिंब है। उनकी यही सोच गुजरात में पहली बार जनजातीय समाज के लिए 'वन बंधु कल्याण योजना' और मछुआरों के लिए 'सागरखेड़ू योजना' में भी दिखाई देती है।

वर्ष 2014 में देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के नेतृत्व का दायित्व दिया। उन्होंने स्वयं को प्रधानसेवक के रूप में सामने रखा और सत्ता के बजाय सेवा को शासन के केंद्र में रखा। सबका साथ-सबका विकासका मंत्र इसी भाव को सशक्त करता है। प्रधान सेवक की यह अवधारणा उनके सार्वजनिक जीवन की उस मूल भावना को व्यक्त करती है, जिसमें सत्ता को अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि सेवा और दायित्व के माध्यम के रूप में देखा गया।

उस समय देश में पक्के घर, शौचालय, नल से जल, एलपीजी गैस कनेक्शन, हर घर तक बिजली, हर गांव तक सड़क, बैंक में खाता, सर्वसुलभ इलाज, ऐसी अनेक मूल सुविधाओं का अभाव था।माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन अभावों को केवल सरकार की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि उस संवेदना के साथ समझा, जो उन्होंने अपने जीवन के क्रम में अनुभव किया।

प्रधानमंत्री जी ने, बाल्यकाल में अपने घर पर, मां को ऐसी अनेक समस्याओं से संघर्ष करते देखा था।उसके उपरांत, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, देशभरमें अपने प्रवास के दौरान भी वह अनेक अनुभवों से गुजरे। इन अनुभवों ने, प्रधानमंत्री जी को नीतियों की स्पष्टता का विजन दिया। यही कारण है कि ऐसे हर काम की सफलता को, और जिस स्केल और स्पीड पर ये कार्यक्रम लागू हुए, उसको सामान्य जन ने अनुभव किया और विश्व ने उसकी सराहना भी की।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्तीय समावेश की सफलता, विश्व के अनेक देशों के लिए मॉडल बन गई है। वर्ष 2014 के बाद,लगभग 60 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए हैं।

वर्ष 2019 में नल से जल पाने वाले ग्रामीण परिवारों की जो संख्या लगभग 17% के आसपास थी, आज वह जल जीवन मिशन के माध्यम से 82% तकपहुंच चुकी है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के माध्यम से गरीबों के लिए4 करोड़ से अधिक पक्के घर भी बनाए गए।इसके अलावा 3 करोड़नए घरों के निर्माण का लक्ष्य लेकर काम जारी है।

देश के नागरिकों का उचित पोषण और नागरिकों का आरोग्य, ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। उनका मत रहा है कि ये ऐसी चुनौतियां हैं, जो गरीबी से मुक्ति और देश के विकास, दोनों को बाधित करती है। इसलिए, 80 करोड़ जरूरतमंद देशवासियों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। बेहतर आरोग्य के लिए, बचाव एवं इलाज, दोनों पर बल दिया गया है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, कुछ राज्यों और कुछ शहरों के बजाय देशभर में किया गया है। साथ ही, 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है।

सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने सुनिश्चित किया कि हर लाभ, उसके असली लाभार्थी तक अवश्य पहुंचे। ऐसी ही नीतियों का परिणाम है कि वर्ष 2013-14 और 2022-23 के बीच, 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में सरकार ने जनकल्याण की भावना से आगे बढ़कर जनसशक्तिकरण की भावना पर जोर दिया है। नारीशक्ति, सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मुद्रा लोन्स, घरों के स्वामित्व और आजीविका कार्यक्रमों से महिलाओं को लाभ मिला है। लगभग 3.5 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को राष्ट्रीय परिवर्तन और राष्ट्रीय सृजन का माध्यम माना है। इसी भाव से बीते 12 वर्षों में युवाओं की फिटनेस, कौशल विकास और उद्यमशीलता पर विशेष बल दिया गया है। युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े अनेक कार्यक्रम लागू किए गए। इससे युवाओं के लिए उद्यमिता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। आज दो लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिनमें लाखों प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

बीते वर्षों में, खेलों के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं और खेलों को फिटनेस और करियर से जोड़ने का संस्थागत प्रयास किया गया है। इससे समाज में खेलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के प्रदर्शन में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

वहीं किसानों के लिए भी आय सहायता, सिंचाई, संस्थागत ऋण, टेक्नोलॉजी और कृषि में विविधता पर बल दिया गया है। पीएमकिसान सम्मान निधि के तहत, 10 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी गई है। इसी प्रकार, पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है।

गरीब कल्याण, शिक्षा, उद्यमिता और मूल सुविधाओं से जुड़े हर कार्यक्रम की सफलता का बहुत बड़ा लाभ उन वर्गों को भी मिला है,

जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे वंचित वर्गों के लिए अवसर बढ़े हैं। बीते वर्षों में ही, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए, शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण की व्यवस्था, सर्व-सपर्शी विकास का बेहतरीन उदाहरण है। जनजातियों में भी जो सबसे पिछड़े जन-जातीय समूह रहे हैं, उनके लिए पहली बार पीएम-जनमन जैसी राष्ट्रीय योजना बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मान्यता दिलाकर, आदिवासी समाज के योगदान के प्रति देश की कृतज्ञता ज्ञापित की है।

प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील और दूरदृष्टि से भरे नेतृत्व का सामर्थ्य, देश और दुनिया ने कोरोना महामारी के वैश्विक संकट में देखा। प्रधानमंत्री जी ने इस महासंकट के दौरान, जिस प्रकार देश को एकजुट किया उसने महामारी से भारत की लड़ाई को बड़ी शक्ति दी।

इस दौरान जिस संकल्प शक्ति के साथ भारत ने अपने टीके बनाए और तेज गति से देशवासियों को टीके लगाए, ये भी उनके संकल्प, सेवाभाव और संवेदनशील नेतृत्व का बहुत बड़ा प्रमाण है।

प्रधानमंत्री जी को आज विश्व, एक विजनरी स्टेट्समैन के रूप में सम्मान के भाव से देखता है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत का रास्ता और मुश्किल कालखंड में भारत को सक्षम नेतृत्व देने का सामर्थ्य है। पिछले एक दशक में

अनेक वैश्विक संकट आए हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशवासियों और सरकार के प्रयासों से भारत का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ता ही गया। हर संकट के बीच आज भारत, विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था है।

पश्चिम एशिया का संकट, सदी के सबसे बड़े संकटों में से एक है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर युद्ध से प्रभावित क्षेत्र पर निर्भर था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में समय पर लिए गए निर्णयों ने, देश को इस संकट का सफलता के साथ सामना करने का सामर्थ्य दिया। संकट के इस समय में, पिछले 12 वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा के लिए उठाए गए ठोस कदम भी बहुत काम आए।

आज अगर देश, वैश्विक संकटों का प्रभावी रूप से सामना कर पा रहा है, तो ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चली रिफॉर्म्स एक्सप्रेस का परिणाम है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने सरकारी योजनाओं में लीकेज की समस्या से मुक्ति दिलाई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देश को लाखों करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा यूपीआई के कारण, हमारे पेमेंट सिस्टम में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। GST जैसे रिफॉर्म के लागू होने से भारत में, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट, की व्यवस्था विकसित हुई है।

पिछले 12 वर्षों में, भारत के विकास का एक उज्ज्वल पक्ष आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रहा है। इस दौरान देश का पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। 2014 में नेशनल हाइवे का जो नेटवर्क करीब 91 हजार किलोमीटर का था, वो अब 1 लाख 46 हजार किलोमीटर से

भी अधिक हो गया है। देश के लगभग पूरे ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क का अबबिजलीकरण हो चुका है।

प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये विश्वास रहा है कि भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन सकता है। भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेश पर निर्भर रहे, वो इस विचार के हमेशा खिलाफ रहे। इसलिए, उनके सेवाकाल में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे सफल अभियान चलाए गए। वर्ष 2014 में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2 लाख करोड़ रुपये के आसपास था, जो 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। बीते दशक में, हमारा रक्षा उत्पादन और निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। इस दौरान देश ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए क्षेत्र में भी कदम रखा है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सेवाकाल की एक बड़ी विशेषता विज्ञान और टेक्नॉलॉजी के प्रति उनका विशेष आग्रह भी रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता इसी का परिणाम है। भारत के फिनटेक इकोसिस्टम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा विश्व, एक उम्मीद के भाव से सराहता है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसानों के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड जैसे अभियानों में भी दिखता है।

प्रधानमंत्री जी ने विश्व को ये संदेश दिया है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है, उसका लाभ पूरी दुनिया को होता है। कोविड के दौरान भारत का वैक्सीन मैत्री अभियानने इसी संदेश को सशक्त किया। भारत ने अपनी कोविड वैक्सीन्स बनाकर, अपने सामर्थ्य को फिर से स्थापित किया। उसके बाद, अनेक देशों को आवश्यक दवाएं और वैक्सीन्स भेजीं।

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वैज्ञानिक और तकनीकी आकांक्षाओं का विस्तार भी हुआ है। चंद्रयान-3 ने भारत को, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनाया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने से भारत की क्षमताओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है।

इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। वर्ष 2014 में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट से भी कम थी। जो आज 160 गीगावाट से अधिक हो चुकी है।

प्रधानमंत्री जी की पहचान एक ईमानदार कर्मयोगी की रही है। राष्ट्रप्रथम के भाव से ही उन्होंने ऐसे अनेक निर्णयों, जो दशकों-दशक तक टाले गए, उनको ज़मीन पर उतारा। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, वन रैंक वन पेंशन लागू करना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाना, श्रम कानूनों को आसान बनाना और अंग्रेजी शासनकाल के कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू करना, ऐसे अनेक प्रमुख कार्य किए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भारत की लक्ष्मण रेखा स्पष्ट रूप से खींची है। वर्ष 2016 में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कोने-कोने में आतंकवादियों और उनके संरक्षकों पर सफलता के साथ हमला किया

गया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। अप्रासंगिक हो चुके सिंधु नदी जल समझौते को अबेयंस में रखने का निर्णय भी इसी रणनीति का हिस्सा है।

माओवादी आतंक भी देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहा है। प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट और संवेदनशील नेतृत्व ने इस खतरे से निपटने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बीते 12 वर्षों के सघन प्रयासों से माओवादी आतंक की कमर तोड़ दी गई है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में, शांति समझौतों, पुनर्वास, विकास और कनेक्टिविटी के प्रयासों के कारण स्थाई शांति को बल मिला है। जम्मू कश्मीर में अशांति, दशकों से देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख चुनौती रही है। आज जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और विश्वास का नया अध्याय लिखा जा रहा है।

पिछले 12 वर्षों में वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज के जटिल वैश्विक परिवेश में, भारत की राय को पूरी गंभीरता से सुना और समझा जाता है। इसका प्रमाण हाल ही में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में देखने को मिला है। भारत में हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, न केवल भागीदारी के हिसाब से सफल रहा, बल्कि हर आशंका को गलत सिद्ध करते हुए, दिल्ली घोषणापत्र जारी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसी प्रकार, वर्ष 2023 में भी भारत ने ऐतिहासिक G-20 सम्मेलन का सफल आयोजन किया। उस समय भी, दिल्ली घोषणापत्र को लेकर अनेक आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों ने उन आशंकाओं को भी टिकने नहीं दिया। भारत, हर मतभेद के बीच एक सेतु और समन्वयकर्ता के रूप में उभरा है।

भारत ने लगातार ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता से रखा है। अपनी G-20 अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को स्थाई प्रतिनिधित्व दिलाने से, भारत पर ग्लोबल साउथ का भरोसा और सशक्त हुआ है।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू जलवायु परिवर्तन को लेकर भी रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में अपने लंबे कार्यकाल से ही इस विषय पर उनकी एक प्रतिबद्धता रही है। प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरण का विषय न मानकर विकास, ऊर्जा, कृषि, पानी और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा विषय माना है। वर्ष 2009 में गुजरात में इस विषय के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने, State Action Plan on Climate Change, ऊर्जा दक्षता, renewable energy और green technology जैसे प्रयासों के माध्यम से विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया।

यही सोच बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बिग कैट अलायंस और मिशन LiFE जैसे अभियानों से और व्यापक हुई। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, ऐसी हर पहल से, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चर्चा में भारत की भूमिकाको सशक्त किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका का एक उदाहरण यह भी है कि विभिन्न देशों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। अब तक 36 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक या राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया है। कोटि-कोटि भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रधानमंत्री जी अब तक 21 बार अन्य देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, देश के विकास के साथ-साथ अपनी विरासत को आगे बढ़ाने पर भी समान रूप से बल दिया गया है। वर्ष 2014 में भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दी। इसके बाद भारत की यह विरासत दुनिया के अनेक देशों तक पहुंची है। इसी प्रकार भारत के प्रयासों से ही, वर्ष 2023 को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट्स घोषित किया गया। ये मोटे अनाज से जुड़ी भारत की विरासत और देश के छोटे किसानों के श्रम का सम्मान था। बीते वर्षों में, दुनिया के अनेक देशों ने भारत की प्राचीन धरोहरें भी लौटाई हैं।

अपनी आस्था और आध्यात्म से जुड़ी विरासत को सशक्त करने का एक और उदाहरण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास भी है। प्राचीन आस्था के इस केंद्र को उसकी विरासत के साथ सहेजते हुए, आधुनिक सुविधाओं का भी विकास किया गया है। इसी क्रम में, जनवरी 2024 में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हुई।

विरासत और आधुनिक भारत के इस मेल की झलक कर्तव्य पथ, नए संसद भवन और सेवा तीर्थ के विजन में भी स्पष्ट होती है। इन स्थानों के निर्माण और विकास के साथ भारतीय परंपराओं और प्रतीकों को भी विशेष स्थान दिया गया है।

अपनी विरासत के साथ जुड़ाव और गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना, ये आज हर देशवासी का प्रण बन चुका है। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर हुए समारोहों ने सभी लोगों को देशभक्ति के सूत्र में बांध दिया। इस महत्वपूर्ण पड़ाव के प्रति राष्ट्र की भावना को देखते हुए, सरकार ने संपूर्ण वंदे मातरम् के गान को अनिवार्य बना दिया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के 25 वर्षों के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता जनभागीदारी रही है। गुजरात के कन्या केलवणी और कृषि महोत्सव जैसे अभियानों से लेकर स्वच्छ भारत और जल संरक्षण तक, कोविड टीकाकरण से लेकर हर घर तिरंगा तक, देश के लोगों ने हर लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

25 वर्ष के इस सेवाकाल में, संस्थाओं के संरक्षण, सुधार और नई संस्थाओं के निर्माण का कार्य भी उल्लेखनीय रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट मत रहा है कि व्यक्ति का प्रभाव अपने समय तक हो सकता है, लेकिन मजबूत संस्थाएं पीढ़ियों तक देश की क्षमता बढ़ाती हैं।

मुख्यमंत्री के रूप में अपने सेवाकाल में उन्होंने WASMO से लेकर BISAG और GIFT City तक, ऐसी संस्थागत क्षमताएं विकसित कीं, जो समय के साथ और बड़ी होती गईं। गुजरात में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, जैसे अनेक संस्थान बनाए गए।

मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा यह विश्वास रहा कि राज्यों की प्रगति ही देश की प्रगति का आधार है। प्रधानमंत्री के सेवाकाल में इसी सोच को सहकारी संघवाद की भावना के साथ राष्ट्रीय

नीति का आधार बनाया गया। राज्यों को अधिक संसाधन, अधिक भागीदारी और विकास की अपनी प्राथमिकताएं तय करने की अधिक शक्ति मिले, इस दिशा में **केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत** की गई।

सहकारी संघवाद, को राष्ट्रीय संस्थानों की भी प्राथमिकता बनाया गया है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग के गठन के पीछे भी ये एक बड़ी प्रेरणा रही है। इससे राज्यों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम नहीं, बल्कि नीति-निर्माण का साझेदार बनाने पर जोर रहा। **GST Council** ने टैक्स के मामले में, **सहकारी संघवाद** को एक स्थायी संस्थागत मंच प्रदान किया। प्रगति प्लेटफॉर्म ने, गवर्नेंस में एक नई कार्य-संस्कृति स्थापित की, जहाँ वर्षों से अटकी परियोजनाओं की समीक्षा होती है और सबके सहयोग से परियोजनाएं पूरी की जाती हैं।

ऐसे अनेक प्रयास दर्शाते हैं कि 25 वर्ष की ये यात्रा केवल **सरकार चलाने की ही नहीं, बल्कि भारत की संस्थागत क्षमता को लगातार मजबूत करने की भी रही है।**

प्रधानमंत्री जी का ये दृढ़ मत रहा है कि विकास और सुशासन का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुंचना ही चाहिए और जो वंचित है, उसे वरीयता मिलनी चाहिए। इसी सिद्धांत पर चलते हुए, सौ से अधिक पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिले और 500 से अधिक ब्लॉक्स को आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया। आज ये आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम, बदली हुई सोच और **सहकारी संघवाद** की सफलता का एक और प्रमाण बन चुका है।

एक और पुरानी सोच, सीमावर्ती गांवों को अंतिम गांव मानने की रही थी। इसके कारण, सीमावर्ती गांवों में विकास का अभाव रहा और पलायन एक बड़ी समस्या बन गई थी। प्रधानमंत्री जी ने, सीमावर्ती गांवों को देश के प्रथम गांव बताया और उसके आधार पर योजनाएं लागू की गईं। इसके परिणास्वरूप, सीमावर्ती गांवों का कायाकल्प हो रहा है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी प्रभावी कदम सिद्ध हो रहा है।

25 वर्षों का ये पड़ाव, ऐसे समय में आया है, जब देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए भारतीय के सामूहिक प्रयास, अर्थात् 'सबका प्रयास', को आवश्यक बताया है। वर्ष 2022 में अमृत महोत्सव के आयोजन ने भी इसी भाव को सशक्त किया है। बीते वर्षों में देश ने जो क्षमताएं विकसित की हैं और जो संस्थान बनाए हैं, वे आज इस राष्ट्रीय प्रयास की मजबूत नींव बन चुके हैं।

आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, ये केंद्रीय कैबिनेट-

- 7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2026 तक सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की सेवा पूरी करने पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती है।
- कैबिनेट, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रसेवा के प्रति उनके समर्पण की सराहना करती है।

- कैबिनेट, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी उस निरंतरता की भी सराहना करती है, जिसमें राष्ट्रहित और जनसेवा को प्राथमिकता दी गई है।
- कैबिनेट, प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति से, हर नागरिक के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन की प्रशंसा करती है। इनमें आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, गरीबों, वंचितों, महिलाओं, युवाओं और किसानों का सशक्तिकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, डिजिटल और तकनीकी क्षमताओं का विकास और भारत की उत्पादन क्षमता को मजबूत करना शामिल है।
- कैबिनेट, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए उन प्रयासों की सराहना करती है, जिनसे सामान्य जन शासन और राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बना है।
- कैबिनेट, राष्ट्रीय हित में हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, संघर्ष वाले क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का अभिनंदन करती है।
- कैबिनेट, दुनिया में भारत की भूमिका और देश की आवाज़ को बुलंद करने में, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की भी सराहना करती है। इसमें ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाना और दुनिया के सामने मौजूद साझा चुनौतियों के समाधान में भारत की भूमिका को मजबूत करना शामिल है।

- कैबिनेट, भारत की विरासत के संरक्षण, आधुनिकीकरण और धरोहरों के सम्मान के लिए, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की भी प्रशंसा करती है।
- कैबिनेट, विकसित भारत के निर्माण के लिए, सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करते रहने का अपना संकल्प दोहराती है।

केंद्रीय कैबिनेट, माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सेवा के लिए अपनी शुभकामना देती है और ये विश्वास जताती है कि उनके कुशल नेतृत्व में देश इसी तरह समृद्ध, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा।
